



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262166
CG-DL-E-30032025-262166

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 30, 2025/चैत्र 9, 1947

No. 107]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 30, 2025/CHAITRA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2025

जांच शुरुआत अधिसूचना

मामला सं. एडी (ओआई)-04/2025

विषय: चीन जन. गण. में उत्पन्न या वहां से निर्यातित 75 डेनियर्स से ऊपर "विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच की शुरुआत।

- फा. सं. 6/04/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटन रोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह और क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995, (इसके बाद 'नियम' के रूप में संदर्भित), एसोसिएशन ऑफ़ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ़ इंडिया (इसके बाद 'आवेदक एसोसिएशन' के रूप में संदर्भित) और ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे आगे 'घरेलू उद्योग' या 'याचिकाकर्ता' कहा जाएगा) ने चीन जन. गण. (जिसे आगे 'विषयगत देश' कहा जाएगा) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "75 डेनियर्स से ऊपर के विस्कोस रेयान फिलामेंट यार्न (वीएफवाई)" (जिसे आगे 'विचाराधीन उत्पाद' या 'विषयगत

वस्तु' या 'पीयूसी' कहा जाएगा) के आयात पर पाटन रोधी जांच शुरू करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे 'प्राधिकारी' कहा जाएगा) के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण भौतिक क्षति हो रही है और उसने संबंधित देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) स्पूल स्पून प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित यार्न को छोड़कर, सीमा शुल्क वर्गीकरण 5403 के तहत वर्गीकृत 75 डेनियर्स से ऊपर विस्कोस रेयान फिलामेंट याम/श्रेड है।

बहिष्करण

4. केवल छोटे बॉबिन पर कढ़ाई धागे का उपयोग करने के लिए तैयार है जिसे कढ़ाई मशीन पर स्थापित किया जा सकता है, और जो सीमा शुल्क वर्गीकरण 5401 के तहत वर्गीकृत है, को वर्तमान जांच के दायरे से बाहर रखा गया है।
5. उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 54 के तहत टैरिफ कस्टम वर्गीकरण के उपशीर्षकों के तहत 5403 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पाद को मुख्य रूप से 54031090, 54033100, 54033200, 54033300, 54033990, 54034110, 54034150, 54034190, 54034911, 54034912, 54034913, 54034919 और 54034990 के तहत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
6. आवेदक ने वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए निम्नलिखित उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति का प्रस्ताव दिया है।

पैरामीटर	प्रस्तावित पीसीएन
टेक्नोलॉजी	क. पीएसवाई
	ख. सीएसवाई
यार्न का डेनियर	वास्तविक डेनियर
ट्विस्टिंग	क. अनट्विस्टेड
	ख. एक बार ट्विस्टेड
	ग. डबल ट्विस्टेड
रंगे हुए/बेरंगे	क. रंगे
	ख. बिना रंगा हुआ

7. वर्तमान जांच के पक्षकार जांच शुरू करने की सूचना के प्रसार के 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि जिन संबंधित वस्तुओं को भारत में डंप करने का आरोप लगाया गया है, वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबंधित देश से आयात किए गए उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशेषताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यो और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। प्राधिकारी नोट करता है कि दोनों प्रथम दृष्टया, तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य

हैं। इसलिए, इस जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं को नियमों के तहत संबंधित देश से आयात की जा रही विषय वस्तुओं के लिए 'वस्तु की तरह' माना जा रहा है।

ग. विषय देश

9. वर्तमान जांच में विषय देश **चीन जन. गण.** है।

घ. जांच की अवधि

10. इस जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच की प्रस्तावित अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 (12 महीने) तक है। क्षति परीक्षा की अवधि 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 - 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च 2024 और पीओआई की अवधि को कवर करती है।

ङ. घरेलू उद्योग और आधार

11. यह आवेदन एसोसिएशन ऑफ मैन-मेड फाइबर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने दायर किया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। मैसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया है कि इसने न तो संबंधित देश से संबंधित वस्तुओं का आयात किया है और न ही संबंधित देश में संबंधित वस्तुओं के किसी निर्यातक या उत्पादक से संबंधित है।

12. उपलब्ध सूचना के आधार पर ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन भारत में इस प्रकार की वस्तु के घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात है। तदनुसार, आवेदन में निहित जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि आवेदन नियमों के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) के प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किया गया है।

च. कथित डंपिंग का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (क) (i) और पाटन रोधी नियम, 1995 के अनुलग्नक- 1 के पैरा 7 के संदर्भ में, चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य चीन जन.गण. में प्रचलित घरेलू बिक्री मूल्य की लागत के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, केवल तभी जब जवाब देने वाले चीनी उत्पादक यह प्रदर्शित करते हैं कि उनकी लागत और मूल्य की जानकारी बाजार संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पैरा (ग) चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाना चाहिए।

14. आवेदक ने यह भी दावा किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था, तीसरे देश में लागत या कीमत से संबंधित आंकड़े या अन्य वैकल्पिक तरीकों का सहारा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्माण उचित लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों को विधिवत समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार संबंधित वस्तुओं के घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

ख. निर्यात मूल्य

15. संबंधित वस्तुओं के लिए निर्यात मूल्य की गणना डीजी सिस्टम लेनदेनवार आयात आंकड़ों के आधार पर की गई है। एक्स-फैक्ट्री स्तरों पर कीमतें बनाने के लिए उचित मूल्य समायोजन का दावा किया गया है ताकि वे सामान्य मूल्य के साथ तुलनीय हो जाएं।

ग. डंपिंग मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना फैक्ट्री स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्टया* यह स्थापित होता है कि संबंधित देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर है। इस प्रकार, प्रथम *दृष्टया* पर्याप्त साक्ष्य हैं कि विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

17. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए विचार किया गया है। घरेलू उद्योग ने कथित पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच अवधि में

विषयगत देश से आयात की मात्रा में निरपेक्ष रूप से वृद्धि देखी गई है तथा यह कुल मांग और उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाटित आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को घाटा, नकद घाटा, ब्याज और कर से पहले घाटा तथा नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मौजूद इन्वेंटरी में तेजी से वृद्धि हुई है। विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं।

ज. पाटन रोधी जांच की शुरुआत

18. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और संबंधित देश में उद्भूत या निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के डंपिंग के संबंध में आवेदक और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति के बीच कारण लिंक और पाटित किए गए आयात, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, विषय देश में उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन रोधी शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक पाटन रोधी जांच शुरू करता है, यदि लगाया जाता है तो यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

झ. प्रक्रिया

19. इस जांच में पाटन रोधी नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

20. सभी संचार ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से नामित प्राधिकारी को भेजे जाने चाहिए dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in एक प्रति adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को भेजी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का कथा भाग खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
21. संबंधित देश में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देश की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभिक अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।
22. कोई अन्य इच्छुक पार्टी भी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और इस दीक्षा अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक सबमिशन कर सकती है।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुतीकरण करने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. इच्छुक पार्टियों को नियमित रूप से व्यापार उपचार महानिदेशालय (<https://www.dgtr.gov.in/>) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि जानकारी के साथ-साथ जांच से संबंधित आगे की प्रक्रियाओं से अवगत और अवगत कराया जा सके।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी नामित प्राधिकारी को निम्नलिखित ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए dd16-dgtr@gov.in और dd12-dgtr@gov.in एक प्रति के साथ adv13-dgtr@gov.in और consultant-dgtr@nic.in को उस तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए, जिस दिन आवेदक द्वारा दायर दस्तावेजों का गैर-गोपनीय संस्करण नामित प्राधिकारी द्वारा प्रसारित किया जाएगा या प्रेषित किया जाएगा नियमों के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि। यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमों के अनुसार अपने निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है।

26. सभी इच्छुक पक्षों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली के जवाब दाखिल करें।
27. जहां एक इच्छुक पार्टी प्रस्तुतियाँ दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगती है, उसे नियम के संदर्भ में इस तरह के विस्तार के लिए पर्याप्त कारण प्रदर्शित करना चाहिए 6(4) विज्ञापन विज्ञापन नियम, 1995 और इस तरह के अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आने चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना

28. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर गोपनीय प्रस्तुतियाँ देता है या जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिस के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
29. इस तरह की प्रस्तुतियों को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को ऐसे सबमिशन का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।
30. गोपनीय संस्करण में वे सभी जानकारी शामिल होंगी जो प्रकृति से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जिसे ऐसी जानकारी का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या जिस जानकारी पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होनी चाहिए, जिसमें गोपनीय जानकारी अधिमानतः अनुक्रमित या खाली हो गई है (जहां अनुक्रमण संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए, जिस जानकारी पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
32. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई जानकारी के सार को उचित रूप से समझने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाला पक्ष यह संकेत दे सकता है कि ऐसी जानकारी सारांशित करने योग्य नहीं है, और नियम 1995 के नियम 7 के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का विवरण, और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस, कि ऐसा सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है, प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
33. इच्छुक पार्टियाँ गोपनीयता के मुद्दों पर अपनी टिप्पणी दे सकती हैं 7 दस्तावेजों के गैर-गोपनीय संस्करण के प्रसार की तारीख से दिन।
34. कोई भी प्रस्तुतिकरण उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया है, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उचित व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वारंट नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
36. प्राधिकारी प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने और संतुष्ट होने पर, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकारी के बिना किसी भी पक्ष को इसका खुलासा नहीं करेगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत इच्छुक पार्टियों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को असहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझती है।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Trade Remedies)

NOTIFICATION

New Delhi, 29th March 2025

INITIATION NOTIFICATION

CASE No. AD (OI) – 04/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Viscose Rayon Filament Yarn (VFY) above 75 deniers” originating in or exported from China PR.

- F. No. 6/04/2025-DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the ‘Rules’), Association of Man-Made Fibre Industry of India (hereinafter referred to as the ‘applicant association’) and Grasim Industries Limited (hereinafter referred to as ‘domestic industry’ or ‘petitioner’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of an anti-dumping investigation on imports of “Viscose Rayon Filament Yarn (VFY) above 75 deniers” (hereinafter referred to as the ‘product under consideration’ or ‘subject goods’ or ‘PUC’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as ‘subject country’).
- The petitioner has alleged that material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject country and has requested for the imposition of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

- The product under consideration (PUC) in the present investigation is ‘Viscose Rayon Filament Yarn/Thread above 75 deniers’ classifiable under customs classification 5403, excluding yarn produced through Spool Spun Technology.

Exclusion

- Only ready to use embroidery thread on small bobbin that can be installed on embroidery machine, and which is classifiable under customs classification 5401, is excluded from the scope of the present investigation.
- The product is classified under the Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) under subheadings of the tariff custom classification as 5403. The product is majorly imported under 54031090, 54033100, 54033200, 54033300, 54033990, 54034110, 54034150, 54034190, 54034911, 54034912, 54034913, 54034919 and 54034990. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

6. The applicant has proposed following product control numbers (PCN) methodology for the product under consideration in the present investigation.

Parameters	Proposed PCN
Technology	a. PSY
	b. CSY
Denier of yarn	Actual denier
Twisting	a. Untwisted
	b. One-time twisted
	c. Double twisted
Dyed/Undyed	a. Dyed
	b. Undyed

7. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of product under consideration and proposed PCN methodology, if any, within 15 days of circulation of the intimation of initiation of the investigation.

B. LIKE ARTICLE

8. The petitioner has claimed that the subject goods which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. The product produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two are *prima facie* technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of this investigation, the subject goods produced by the petitioner in India are being treated as 'like article' to the subject goods being imported from the subject country under the Rules.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The subject country in the present investigation is **China PR**.

D. PERIOD OF INVESTIGATION

10. The proposed period of investigation (POI) adopted by the Authority for this investigation is from 1st October 2023 – 30th September 2024 (12 months). The injury examination period covers the periods 1st April 2021 – 31st March 2022, 1st April 2022 – 31st March 2023, 1st April 2023 – 31st March 2024 and the POI.

E. DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

11. The application has been filed by the Association of Man-Made Fibre Industry of India. Grasim Industries Limited has provided data relating to injury to the domestic industry. M/s Grasim Industries Limited has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject country nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country
12. On the basis of the information available, the production of the Grasim Industries Limited accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. Accordingly, on the basis of the information contained in the application, the Authority is *prima facie* satisfied that the application has been made by or on behalf of the domestic industry in terms of the provisions of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules.

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal value for China PR

13. The applicant has claimed that in terms of Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol and Para 7 of Annexure-I to the Anti-Dumping Rules, 1995, the normal value for Chinese producers may be determined based on the cost of domestic selling price prevailing in China PR, only if the responding Chinese producers demonstrate that their cost and price information are based on market driven principles and allow for fair comparison in terms of paras 1 to 6 of Annexure-I to the AD Rules, failing which, normal value for Chinese producers must be determined based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the Rules.

14. The applicant has also claimed that the data relating to cost or price in market economy third country or recourse to other alternative methods are not available. The normal value has been, thereby, constructed based on the best estimates of the cost of production of the domestic industry of the subject goods as per the best information available after duly adjusted the selling, general and administrative expenses, with reasonable profit.

b. Export price

15. The export price for the subject goods has been computed based on the DG System transaction wise import data. Appropriate price adjustments have been claimed to make prices at ex-factory levels so that they become comparable with normal value.

c. Dumping margin

16. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject country is above the *de minimis* level. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration is being dumped in the domestic market of India by the exporters from the subject country.

G. EVIDENCE OF INJURY AND CAUSAL LINK

17. Information furnished by the domestic industry has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The domestic industry has furnished evidence with respect to the injury suffered because of the alleged dumped imports. The volume of imports from the subject country has shown an increase in absolute terms in the period of investigation and it is a significant share of total demand and production. The dumped imports are suppressing the prices of the domestic industry. As a result, the domestic industry has incurred losses, cash losses, loss before interest and tax and negative return on capital employed. The inventories with the domestic industry sharply increased over the injury period. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject country.

H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

18. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant and the domestic industry concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from subject country and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

19. The provisions stipulated in Rule 6 of the anti-dumping rules shall be followed in this investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

20. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
21. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
22. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further directed to regularly visit the official website of the Directorate General of Trade Remedies (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay updated and apprised with the information as well as further processes related to the investigation.

K. TIME LIMIT

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the following email addresses dd16-dgtr@gov.in and dd12-dgtr@gov.in with a copy to adv13-dgtr@gov.in and consultant-dgtr@nic.in, within 30 days from the date on which the non-confidential version of the documents filed by the applicant would be circulated by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority